Title : Need of procurement of paddy by the government procurement centres from farmers in time.

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे जल्दी बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं उत्तर प्रदेश के धान के कृषकों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जो किसान धान की कटाई-मढ़ाई कर के अपने घरों को ले गए हैं, आज उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है और वे बहुत परेशान हैं। विशेषरूप से जो सरकारी क्रय-विक्रय केन्द्र खोले गए हैं, वहां पर किसानों को टोकन देने में देरी की गई है। दूसरी बात यह है कि इसमें एक व्यवस्था यह की गई है कि जो लघु और सीमांत कृषक हैं, केवल वही सरकारी क्रय-विक्रय केन्द्रों पर अपना धान ले जाएंगे। जो बाकी बड़े कास्तकार हैं, वे अपना धान कहां ले जाएंगे, यह एक बहुत बड़ी दिक्कत किसानों के सामने खड़ी है?

महोदय, जो टोकन दिया गया है, वह बाद का दिया गया है। उसमें तुरन्त और तत्काल उनके धान को बेचने की व्यवस्था नहीं की गई है। क्रय-विक्रय केन्द्र पर किसान के धान को तुरन्त बेचकर पैसा देने की व्यवस्था नहीं की गई है, बल्कि उन्हें मई, जून और जुलाई में समय दिया गया है, जिससे किसान बहुत परेशान हैं। ये किसान जब अपना धान क्रय-विक्रय केन्द्र पर बेचते हैं, तो उन्हें वाजिब मूल्य मिलता है। उसके बाद वे रबी की फसल, चाहे गेहूं हो या आलू हो, वह बोकर अपना पेट पालते हैं, लेकिन यह विकट स्थिति है, क्योंकि उसे उसकी फसल का पैसा अभी दिया ही नहीं गया है और अगले साल मई, जून और जुलाई का समय दिया गया है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सरकार इसे गम्भीरता से ले और जल्दी से जल्दी क्रय-विक्रय केन्द्रों पर इन किसानों को चाहे फिर वे सीमान्त, लघु, मध्यम या बड़े कास्तकार हों, उनके धान को लेकर उन्हें वाजिब मूल्य दें, तभी किसान आगे की यानी रबी की खेती करेगा। इससे किसान भी खुशहाल होगा और देश भी खुशहाल होगा। इन्हीं बातों के साथ, मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं।